

नौकरियों में स्थानीय आरक्षण

प्रलिस के लयः

नौकरयों में स्थानीय आरक्षण, अनुच्छेद 14,16,19, [हरयऱणा राज्य स्थानीय उममीदवारों का रोजगार अधनऱयऱम, 2022](#), आंदोलन की स्वतंत्रता

मेन्स के लयः

नौकरयों में स्थानीय आरक्षण और नहऱतऱरथ

चरचा में कयों?

पछऱले वरषों की तुलना में नौकरयों में स्थानीय आरक्षण कानून के परणऱमस्वरूप राज्य को नई नवऱश परयऱोजनाएँ कम प्राप्त हुई हैं, जसकी वजह से राष्ट्र में नई नवऱश परयऱोजनाओं में राज्य की हसऱसेदारी पछऱले वरष के 3% से घटकर 2022-23 में 1.06% हो गई, जो छह वरषों में सबसे कम है।

- हरयऱणा ने वरष 2022 की शुरुआत में [हरयऱणा राज्य स्थानीय उममीदवारों का रोजगार अधनऱयऱम, 2022](#) को लागू कयऱ था, जसमें 30,000 रुपए तक मासकऱ वेतन वाली नऱजी क्षेत्र की नौकरयों में से 75% स्थानीय लोगों हेतु आरक्षणऱतऱ है।

हरयऱणा राज्य स्थानीय उममीदवारों का रोजगार अधनऱयऱम, 2022:

परचयः

- इसके तहत 10 या अधकऱ कर्मचारयों वाली फरर्मों को 30,000 रुपए परतमाह वाली सभी नौकरयों में से 75% राज्य के अधवऱसी उममीदवारों के लयऱ आरक्षणऱतऱ करने की आवशयकता है।
- इन सभी नयऱकताओं के लयऱ शर्म वभऱग, हरयऱणा की आधकऱरकऱ वेबसाइट पर उपलब्ध नामतऱ पोर्टल परसकल मासकऱ वेतन या 30,000 रुपए से अधकऱ वेतन नहीं पाने वाले अपने सभी कर्मचारयों को पंजीकृत करना अनवऱर्य होगा।

अन्य राज्यों में कयऱ गए इसी प्रकार के परयासः

- आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड सहऱतऱ अन्य राज्यों में भी नवऱसयों के लयऱ रोजगार आरक्षण वधऱयक अथवा कानूनों की घोषणा की गई है।
- रोजगार कोटा वधऱयक के तहत आंध्र प्रदेश के नवऱसयों के लयऱ तीन-चौथाई नऱजी नौकरयऱ आरक्षणऱतऱ हैं, जसऱ वरष 2019 में राज्य की वधऱनसभा द्वारा अनुमोदतऱ कयऱ गया था।

नौकरयों में स्थानीय आरक्षण के लाभ एवं नुकसानः

लाभः

- संवैधानकऱ रूप से मान्यः भारतीय संवधऱन के अनुच्छेद 16 के तहत अधवऱस और नवऱस के आधार पर आरक्षण पर परतबऱध नहीं है। यह स्थानीय नौकरयों में स्थानीय लोगों को पहले अवसर परदान करने के लयऱ संवैधानकऱ रूप से मान्य परतीत होता है कयोंकऱ प्राथमकऱ तौर पर यही लोग नौकरी सृजन करने वाली कंपनयों के कारण पडने वाले सभी परतकऱल परभावों को सहन करते हैं।
- समानताः स्थानीय नौकरयों में आरक्षण समाज के सबसे कमजोर वरग को समानता परदान करता है, कयोंकऱ आरक्षण केवल नमऱन स्तर की नौकरयों तक ही सीमतऱ है और यह भारत के संवधऱन के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समान संरक्षण की भावना के अनुसार है।
- बेरोजगारी के लयऱ उपयुक्त समाधानः बेरोजगारी और स्थऱर रोजगार सृजन की समस्या को देखते हुए स्थानीय नौकरयों में आरक्षण एक उपयुक्त समाधान है।
- भारत के संवधऱन में अनुच्छेद 371D और E के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लयऱ उनकी वशेष परसऱथऱतऱयों को देखते हुए नौकरयों और शकऱषा हेतु वशेष प्रावधान है। अतः बेरोजगारी की स्थऱतऱ में स्थानीय नौकरयों में आरक्षण उचतऱ और भारत के संवधऱन के वशेष प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त परतीत होता है।

- **स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** जब कंपनियों स्थानीय लोगों को काम पर रखती हैं, तो वे अपनी कमाई स्थानीय अर्थव्यवस्था में खर्च करती हैं, जो रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास में मदद कर सकता है।
 - स्थानीय लोगों को काम पर रखने का मतलब है कि कंपनियों को कर्मचारियों के स्थानांतरण का खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा। यह उनकी परचालन लागत को कम करने में मदद कर सकता है, जैसे कम कीमतों के रूप में ग्राहकों पर डाला जा सकता है।
- **उत्पादकता में सुधार:** स्थानीय कर्मचारियों की स्थानीय भाषा, संस्कृति और कारोबारी माहौल से परिचित होने की अधिक संभावना है, जो उनकी उत्पादकता और दक्षता में सुधार करने में मदद कर सकता है।

■ चर्चाएँ:

- **नविशकों के पलायन में वृद्धि:** यह ऑटो, आईटी जैसे क्षेत्रों में बड़े घरेलू और बहुराष्ट्रीय नविशकों के पलायन को गति प्रदान कर सकता है जो अत्यधिक कुशल जनशक्ति पर निर्भर हैं।
 - हरियाणा के मामले में वर्ष 2022 में कया गया नविश लगभग 56,000 करोड़ रुपए से 30% गरिकर 39,000-करोड़ रुपए हो गया, स्थानीय आरक्षण कानून के कारण यह वर्ष 2022-23 में नई नविश परियोजनाओं के मामले में नौवें सर्वश्रेष्ठ राज्य से 13वें स्थान पर पहुँच गया।
- **मौजूदा उद्योगों को प्रभावित करना:** राज्य के अन्य क्षेत्रों से राज्य में जनशक्ति संसाधनों की मुक्त आवाजाही को रोकने एवं स्थायी नविसियों के मुद्दे उठाने से राज्य में मौजूदा उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
 - यह तकनीकी दृष्टियों और अन्य उद्योगों को अपना आधार हरियाणा से दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करने तथा राज्य के मौद्रिक संसाधनों को कम करने में भूमिका निभा सकता है।
- **कुशल प्रतभा की कमी उत्पन्न कर सकता है:** गति और प्लेटफॉर्म कंपनियों पर आरक्षण लागू करने से प्रतभा की कमी हो सकती है।
- **संवधान के विरुद्ध:** भारत का संवधान अनेक प्रावधानों के माध्यम से देश में कहीं आने-जाने की स्वतंत्रता और रोजगार की गारंटी देता है।
 - अनुच्छेद 14 जन्म स्थान पर ध्यान दयि बना कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है।
 - अनुच्छेद 15 जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रक्षा करता है।
 - अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में जन्मस्थान आधारित भेदभाव की गारंटी नहीं देता है।
 - अनुच्छेद 19 सुनिश्चित करता है कि नागरिक भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आ-जा सकते हैं।

आगे की राह

- आरक्षण नीतिको इस तरह से लागू किया जा सकता है जिससे देश में जनशक्ति संसाधनों के मुक्त आवागमन में बाधा न आए।
- राज्य में अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिये आरक्षण नीतिकी समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है।
- यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कलिया गया कोई भी नीतित नरिण्य भारत के संवधान के अनुपालन में है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।
- स्थानीय लोगों के लिये नौकरी (JRFL) हेतु विभिन्न राज्य सरकारों के पर्याप्तों का सबसे अच्छा तरीका आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना है और कौशल प्रशिक्षण तथा उचित शिक्षा के साथ युवाओं के लिये पर्याप्त नौकरी के अवसर प्रदान करना है, जो मुख्य क्षेत्रों के रूप में जनता को मुफ्त बाज़ार में प्रतस्पर्द्धा करने में सक्षम बनाता है।

स्रोत: द हट्टि